सुराज के किसान सम्मेलनों में भी जाएंगे मुख्यमंत्री

कलेक्टरों से मनरेगा भुगतान और पेयजल की भी जानकारी ली

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 6 अप्रैल। ग्रामीणों की समस्याओं का यथासंभव तुरंत निराकरण करते हुए उन्हें आम जिंदगी से जुड़ी प्रमुख योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी छठवें ग्राम सुराज अभियान की तैयारियां तेजी से चल रही है।

मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में बुधवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 18 में से 14 जिलों के कलेक्टरों की बैठक लेकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि ग्राम सुराज अभियान के दौरान हाट-बाजारों और बड़े गांवों में आयोजित होने वाले कृषक सम्मेलनों में किसानों को समितियों में समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान के लिए बोनस का भी वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने अप्रैल माह में किसानों को 250 करोड़ रूपए का बोनस बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उल्लेखनीय है कि बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में घोषित उप चुनाव की आचार संहिता के परिपालन में उस इलाके के चार जिलों बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), नारायणपुर और बीजापुर में ग्राम सुराज अभियान फिलहाल स्थगित रहेगा। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शेष 14 जिलों में अभियान की तैयारियों से जुड़े सभी विषयों पर कलेक्टरों से बातचीत की। डॉ. सिंह ने इस मौके पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत निर्माण कार्यों और मजदूरी भुगतान की स्थिति और गर्मियों में अगले तीन माह के लिए सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दो चरणों में आगामी 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक और 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलने वाले ग्राम सुराज अभियान में वैसे तो वे सभी जिलों में किसी ने किसी गांव का हेलीकॉप्टर से अचानक दौरा करेंगे, लेकिन इस दौरान वे प्रत्येक जिले के किसी एक प्रमुख स्थान पर किसानों के सम्मेलन में घोषित रूप से भी पहुंचेंगे।

वीडियो कांफ्रेंसिंग

ग्राम सुराज अभियान में खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं का समुचित लाभ दिलाने के लिए सभी जिलों के हाट-बाजारों या बड़े गांवों में किसान रथों के भ्रमण के साथ-साथ किसानों के सम्मेलन भी होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भू-जल संरक्षण की दृष्टि से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक गांवों में कम से कम एक तालाब निर्माण और तालाब गहरीकरण का कार्य भी मंजूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि मनरेगा में मजदूरी भुगतान नियमित रूप से हो और यह भी सुनिश्चित किया जाए। वैसे तो राज्य में पिछला मानसून आम तौर पर ठीक-ठाक रहा, लेकिन जिन इलाकों में बारिश की कुछ कमी हुई, वहां अगर भू-जल स्तर नीचे चला गया हो तो ऐसे गांवों को चिन्हांकित कर वहां हैण्डपम्पों में राईजर पाईप बढ़ाने का काम युध्द स्तर पर किया जाए। अगर कहीं तालाबों को नहरों से भरने की जरूरत हो तो सिंचाई जलाशयों में पानी की उपलब्धता बनाए रखकर इसके लिए भी कदम उठाए जाए।

डॉ. सिंह ने कहा कि पेयजल, बिजली और शौचालय सुविधा के लिए शेष रह गए स्कूलों में इनकी व्यवस्था के लिए भी त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में ग्राम सुराज के लिए चल रही तैयारियों का ब्यौरा दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव पी. जॉय उम्मेन, प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग पी. रमेश कुमार, सचिव सामान्य प्रशासन श्रीमती निधि छिब्बर, ऊर्जा सचिव अमन कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव सुबोध कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।